

नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना

एक मजबूत एवं विकसित राष्ट्र का आधार है। बिना मजबूत अर्थतंत्र के सक्षम एवं सशक्त स्थापित नहीं हो सकता। अतः वित्तीय हितों का संधान करना राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता है ताकि राज्य के दीर्घकालिक हितों का संवर्धन हो सके। लोक हित में ही राष्ट्र हित निहित होता है अर्थात् लोक हित ही राष्ट्र का धर्म है। इसी अवधारणा के अन्तर्गत शासकीय कार्य के कार्मिकों के हितों के संरक्षण हेतु ही राज्यों द्वारा अनेक योजनाएं क्रियान्वित की गयीं। कार्मिकों के दीर्घकालिक सेवाओं के फलस्वरूप उनके सेवाकाल के उपरान्त उन्हें पेंशन सुविधा प्रदान किया जाना प्रमुख है। उक्त पेंशन सुविधा को क्रमशः व्यापक आधार देते हुए कार्मिकों की मृत्यु के उपरान्त उनके परिवार के अर्ह सदस्यों को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ प्रदान किया गया। नव परिभाषित पेंशन योजना के क्रियान्वयन के पूर्व केन्द्र सरकार द्वारा लाया गया पेंशन योजना ही प्रभावी थी जिसमें सेवानैवृत्तिक/सेवारत मृत्यु की दशा में कार्मिकों को पेंशन प्राप्त थी। किन्तु इस लाभादायी पेंशन योजना की भी कुछ सीमायें रहीं। इस योजना का कवरेज संगठित क्षेत्र तक सीमित रहा है और असंगठित क्षेत्र में श्रमशैली की बहुसंख्या वृद्धावस्था में वित्तीय सहायता के अभाव में नागरिक साधनों से आच्छादित नहीं है। विश्व की प्रौढ़ जनसंख्या का लगभग आठवाँ हिस्सा 60 वर्ष की आयु से अधिक आयु की जनसंख्या का अधिकांश किसी संगठित पेंशन योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं है वरन् वे अपने अर्जनों और अपनी संतान से प्राप्त धन पर निर्भर रहते हैं। भारत में कार्यशील जनसंख्या का केवल लगभग 12 प्रतिशत हिस्सा ही सेवानैवृत्तिक पेंशन योजना से किसी रूप में आच्छादित है। उच्च प्रशासनिक लागत और आय प्राप्ति के निम्न वास्तविक दर के कारण मौजूदा प्रणाली अत्यंत अवहनीय (Unsustainable) मौजूदा पेंशन प्रणाली की सुधार पेंशन की देनदारियों के कारण सरकार और अन्य नियोक्ताओं पर पड़े वित्तीय बोझ में हुई अत्यधिक वृद्धि से और घटती गयी। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के सम्बन्ध में कुल पेंशन देनदारी सकल घरेलू उत्पाद के 1993-94 के 6.6% से बढ़कर 2002-03 के 1.66 के बराबर हो गया। इसी अवधि में निवल कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में कुल पेंशन देनदारी 9.7% से बढ़कर 12.68 प्रतिशत हो गयी है। राज्य सरकारों के सम्बन्ध में 1995-96 से 2000-2001 की अवधि में पेंशन व्यय में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धिदर 27.1% से बढ़कर 100% तक पहुँच गया। राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में राज्यों का पेंशन व्यय 1991-92 के 5.4% से बढ़कर 2000-01 के 10 प्रतिशत से अधिक हो गया।

2000 से 2007 के मध्य भारत में पेंशन प्रणाली में सुधार के प्रयास किये गये। पेंशन एवं पेंशनयोगी कल्याण विभाग, कार्मिक पेंशन व लोकशिकायत मंत्रालय द्वारा गठित उच्चस्तरीय विशेष-ज्ञ (H.L.E.G.) की अध्यक्षता में 2000-01 के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई वृद्धावस्था सामाजिक एवं आय सुरक्षा (OASIS) परियोजना क्रमशः सरकारी कर्मचारियों और असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन सुधार की राह के दो मील के पत्थर के रूप में सामने आई। OASIS कमेटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट जनवरी, 2000 में प्रस्तुत की। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में विश्व देशों में कार्यान्वित पेंशन योजनाओं एवं सुधार कार्यक्रम का अनुशीलन एवं विशेष दल की रिपोर्टों तथा OASIS कमेटी की रिपोर्टों पर गहन विचार-विमर्श उपरान्त निर्णय लेते हुए केन्द्र सरकार ने 2003-04 के बजट में नवपरिभाषित पेंशन योजना की सिविल सेवाओं एवं अन्य कर्मचारियों हेतु घोषणा की गयी। भारत सरकार ने 23 अगस्त, 2003 को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) की स्थापना की ताकि पेंशन निधि की स्कीमों और उससे जुड़े अथवा आनुषांगिक मामलों में अतिदाताओं के हितों के संरक्षण हेतु पेंशन निधियों की स्थापना, विकास और विनियमन करते हुए वृद्धावस्था आय सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा सके। प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और अधिक से अधिक 5 सदस्य होंगे जिनमें से कम से कम 3 सदस्य पूर्णकालिक होंगे जिनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जायेगी। पेंशन सम्बन्धी सुधारों की ओर पहले कदम के रूप में भारत सरकार ने सुस्पष्ट लाभादायी पेंशन से हटते हुए सुस्पष्ट अंशदान आधारित पेंशन को अपना लिया है और इसे 01 जनवरी, 2004 को अपनी नयी पेंशन योजनाओं को लागू करने के लिए विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 22.12.2003 के द्वारा अनिवार्य बना दिया है।

24 तक 28 वर्ष की आयु के पेंशनियों के लिए नयी पेंशन प्रणाली अधिसूचित कर दी है। 01 अप्रैल 2009 से एन. डी. आर. स्वैच्छिक आधार पर प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध है। 24 कोई 30 भारतीय नागरिक इस योजना के तहत अपना खाता खोलकर धनराशि का निवेश कर सकता है जिससे कि उसे वृद्धावस्था सुरक्षा हेतु पेंशन प्राप्त हो सके। कोई 30 भारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य हो, एन. डी. आर. में अपना खाता खोल सकता है इसके लिए उसे PFRDA द्वारा अधिकृत संस्था Point of Presence (P.O.Ps) में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस योजना के अन्तर्गत न्यूनतम अंशदान 500/- रुपये निर्धारित है तथा एक वर्ष में न्यूनतम

6000/-)। कम से कम चार अंशदान के माध्यम से जमा किया जाना है। इसके अन्तर्गत अभिदाता अपनी धनराशि का निवेश “Active Choice” और “Auto Choice” के माध्यम से PFRDA द्वारा निर्धारित 6 फण्ड मैनेजर्स के माध्यम से कर सकता है। समाज के कमजोर एवं विपन्न वर्गों की सामाजिक सुरक्षा हेतु PFRDA द्वारा एन. ए. आर. लाइट योजना प्रारम्भ की गई है। एन. ए. आर. के प्रसार हेतु भारत सरकार द्वारा स्वावलम्बन योजना वित्तीय वर्ष 2010-11 के अंतर्गत की गई है। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के ऐसे नागरिक जो वर्ष 2010-11 के एन. ए. आर. खाता खोलते हैं एवं कम से कम 1000 एवं अधिकतम वर्ष में 12000)। (अर्थात् 12 लाख) (3000) (अर्थात् 3 लाख) मिलकर) जमा करते हैं उसे सरकार द्वारा आगामी 3000) (अर्थात् 3 लाख) प्रतिवर्ष की सहायता अंशदान के रूप में दी जायेगी।

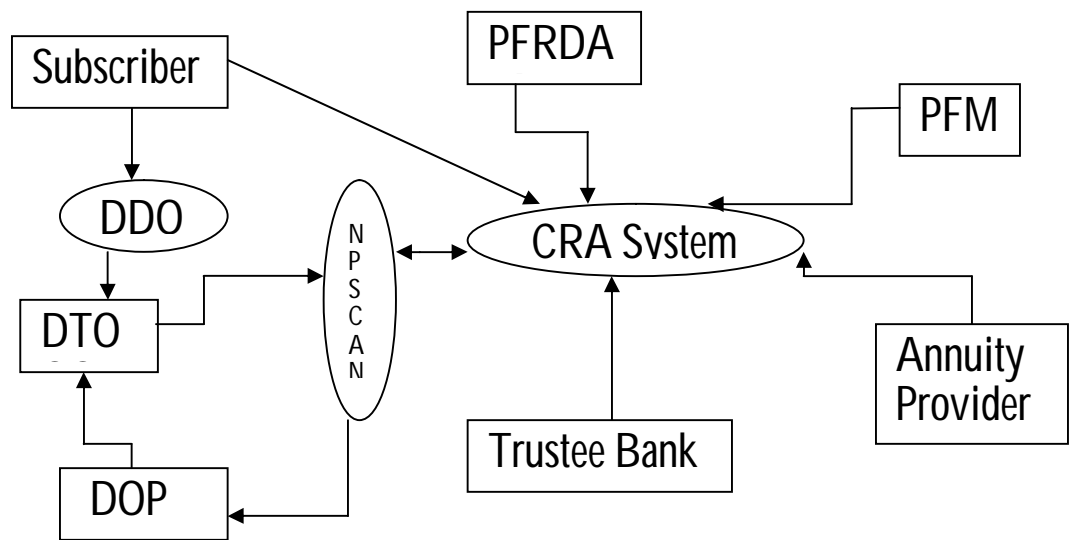
नई पेंशन प्रणाली की मुख्य विशेषताएं और संरचना

- एन.पी.एस. संरचना पारदर्शी एवं बेव समर्थित है यह अभिदाता के एन. ए. आर. के अन्तर्गत अपने निवेशों एवं धनराशियों का अनुश्रवण करने हेतु समृद्ध बनायी गयी और पेंशन निधि प्रबंधन और निवेश विकल्प का चयन अभिदाता के पास होगा। इस ढांचे में अभिदाता को निवेश विकल्पों के साथ पेंशन निधियों को बदलने की भी अनुमति दी गयी है।
- नई पेंशन प्रणाली स्पष्ट अंशदानों पर आधारित होगी। अंशदानों के संग्रहण हेतु इसमें बैंकों की शाखाओं और डाकघरों आदि के मौजूदा तंत्र का प्रयोग किया जाएगा। रोजगार और/ अथवा स्थान परिवर्तित हो जाने के कारण संग्रहणों के अंतरण बिना किसी बाधा के किये जाएंगे। यह निवेश विकल्पों और निधि प्रबंधकों के बीच की भी पेशकश करेगी। यह नई पेंशन प्रणाली स्वैच्छिक होगी।
- परन्तु यह प्रणाली, केन्द्र सरकार की सेवा में आने वाले नए प्रवेशकर्ताओं (आर. आर. 1) (अर्थात् 1) के सिवाए) के लिए अनिवार्य होगी। मासिक अंशदान वेतन और मंहगाई अंश का 10 प्रतिशत होगा जो कर्मचारी द्वारा अदा किया जाएगा और केन्द्र सरकार द्वारा समतुल्य राशि दी जाएगी। तथापि, उन व्यक्तियों के संबंध में जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, सरकार की तरफ से कोई अंशदान नहीं होगा। अंशदान और उन पर प्रति फलों को एक अनाहरणीय पेंशन खाते में कहा जायेगा, में जमा कराया जाएगा। परिश्रम पेंशन और सामान्य अविष्य निधि के मौजूदा प्रावधान केन्द्र सरकार की सेवा में आने वाले नए प्रवेशकर्ताओं को उपलब्ध नहीं होंगे...
- पेंशन खाते के अतिरिक्त, प्रत्येक व्यक्ति अपनी पसंद का स्वैच्छिक टियर-II आहरणीय खाता रख सकता है। सरकार इस खाते में कोई अंशदान नहीं करेगी। इन परिसंपत्तियों की व्यवस्था उसी तरीके से होगी जैसे पेंशन की होती है। इस खाते में संग्रहणों को किसी भी कारण वित्त निकास जा सकता है।
- व्यक्ति सामान्यतया 60 वर्ष की आयु में अथवा बाद में इस पेंशन प्रणाली से बाहर निकल सकता है। व्यक्ति निकलते समय उस व्यक्ति से अपेक्षित होगा कि वह पेंशन धन का कम से कम 40 प्रतिशत वार्षिकी की खरीद में निवेश करे। सरकारी कर्मचारियों के मामले में यह वार्षिकी सेवानिवृत्त के समय कर्मचारी को जीवनपर्यंत वार्षिकी और उसके पति/पत्नी के लिए पेंशन की व्यवस्था करेगी। वह व्यक्ति शेष पेंशन धन को एकमुश्त रूप में प्राप्त करेगा जिसका उपयोग किसी भी तरह से करने के लिए वह स्वतंत्र होगा। व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु से पहले पेंशन प्रणाली छोड़ने की छूट प्राप्त होगी। लेकिन इस मामले में अनिवार्य वार्षिकीकरण पेंशन धन का 80% होगा।
- चयन के लिए एक या अधिक केन्द्रीय अखिलेखपाल (CRA), अनेक पेंशन निधि प्रबंधक (पी.ए.ए.ए.ए.) होंगे जो विभिन्न श्रेणियों की स्कीमों की पेशकश करेंगे।
- पेंशन निधि (PFM, CRA) पिछले कार्यनिष्पादन और नियमित निवल परिसंपत्ति मूल्य (NAV) के आधार में आसानी से समझी जा सकने वाली सूचना देंगे ताकि व्यक्ति अपनाई जाने वाली योजना के अंतर्गत निर्णय ले सके।

PFRDA ने फण्ड मैनेजर के कार्यों की निगरानी के लिए भारतीय न्यास अधिनियम 1982 के अन्तर्गत एक न्यास (एन. ए. ए. ए. ए. ए.) का गठन किया है। NPS एक्ट द्वारा फण्ड मैनेजर एवं नई पेंशन योजना से सम्बन्धित अन्य संस्थाओं के कार्यों का पर्यवेक्षण किया जाएगा। PFRDA द्वारा केन्द्र सरकार के नवप्रवेशकों को खाता संख्या आवंटित करने एवं कटौतियों के रखरखाव हेतु नेशनल सिक्सोरिटीज डिपोजिटरी एन.एस.डी.एल. (NSDL) को सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेन्सी (CRA) नियुक्त करते हुए अनुमोदित कर लिया है। PFRDA के केंद्रीय कार्मिकों हेतु L.I.C. Pension Fund Limited, SBI Pension Funds Limited, UTI Retirement Solutions Limited को प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग के माध्यम से पेंशन निधि प्रबन्धक (Fund Manager) नियुक्त करते हुए अनुमोदित किया गया है। असंगठित क्षेत्र (आवृत्त भारतीय नागरिकों के लिए) ICICI Prudential Pension Funds Management Company Limited, IDFC Pension Fund Management Company Limited, Kotak Mahindra Pension Fund Limited, Reliance Capital Pension Fund Limited, SBI Pension Funds Limited, UTI Retirement Solutions Limited को फण्ड मैनेजर नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त अशिलेखों के रख-रखाव हेतु स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया को कस्टोडियन (Custodian) नियुक्त किया गया है। धनराशि के रख-रखाव हेतु "बैंक आफ इण्डिया" को ट्रस्टी बैंक के रूप में अनुमोदित किया गया। इस प्रकार नई पेंशन योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित संस्थाएं (Entities) होंगी-

- (क) सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेन्सी
- (ख) पेंशन फण्ड मैनेजर्स
- (ग) एन.एस.डी.एल.
- (घ) एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर
- (ङ) कस्टोडियन
- (च) नोडल आफिसर
- (ज) ए.पी.एस.आइ.ए.

सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेन्सी का कार्यात्मक ढांचा निम्नवत होगा:-



CRA का कार्य निम्नवत होगा।

- (i) †‡¸¸¸¸ (Subscriber) ‡¸¸¸‡¸¸¸ कार्यदायी संस्थाओं का CRA सिस्टम में पंजीकरण करना।
- (ii) †‡¸¸‡¸¸‡¸¸ को एकल खाता संख्या आवंटित करना।
- (iii) †‡¸¸‡¸¸‡¸¸ का लेखाजोखा रखना।
- (iv) †‡¸¸‡¸¸‡¸¸ को खाते के सं‡¸¸‡¸¸‡¸¸ में लेखा पर्ची जारी करना।
- (v) †‡¸¸‡¸¸‡¸¸ एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं को सेवाएं प्रदान करना।
- (vi) †‡¸¸‡¸¸‡¸¸ की समस्याओं का समाधान करना।
- (viii) PFRDA को सामयिक रिपोर्ट देना।

CRA में निम्नलिखित Modules होंगे

- (i) नोडल आफिस का पंजीकरण
- (ii) †‡¸¸‡¸¸‡¸¸ का पंजीकरण
- (iii) †‡¸¸‡¸¸‡¸¸ के खाते का रखरखाव
- (iv) †‡¸¸‡¸¸‡¸¸ के देयों का सेटलमेन्ट
- (v) †‡¸¸‡¸¸‡¸¸ की शिकायतों/कठिनाईयों के निस्तारण हेतु प्र‡¸¸‡¸¸‡¸¸ प्रणाली
- (vi) †‡¸¸‡¸¸‡¸¸ †‡¸¸‡¸¸‡¸¸ तथा काल सेन्टर

पेंशन निधि प्र‡¸¸‡¸¸‡¸¸ के कार्य-

- (i) PFRDA ‡¸¸‡¸¸‡¸¸ योजनाओं के सं‡¸¸‡¸¸‡¸¸ में अनुमोदन प्राप्त करना ‡¸¸‡¸¸‡¸¸ इसका पंजीकरण CRA से कराना।
- (ii) †‡¸¸‡¸¸‡¸¸ को पेंशन निधि योजना (PFS) के सं‡¸¸‡¸¸‡¸¸ में प्रस्ताव देना।
- (iii) ‡¸¸‡¸¸‡¸¸ ‡¸¸‡¸¸‡¸¸ को/से पेंशन निधि की धनराशि जमा/प्राप्त करना।
- (iv) †‡¸¸‡¸¸‡¸¸ की पेंशन निधि को अ‡¸¸‡¸¸‡¸¸ को प्रस्तावित योजना में जमा कर निधि का प्र‡¸¸‡¸¸‡¸¸ करना।
- (v) दैनिक आधार पर नेट एसेट वैल्यू (NAV) की सूचना उपल‡¸¸‡¸¸‡¸¸ कराना।
- (vi) PFRDA को प्रगति आख्या प्रेषित करना।

‡¸¸‡¸¸‡¸¸‡¸¸ के कार्य-

- (i) नोडल आफिस से पेंशन निधि प्राप्त करना..
- (ii) CRA के निर्देश पर Fund Managers को /से पेंशन निधि की धनराशि जमा/‡¸¸‡¸¸‡¸¸ करना।
- (iii) आहरित पेंशन निधि की धनराशि को CRA के निर्देश पर एन्वुटी सर्विस ‡¸¸‡¸¸‡¸¸ (ASPS) को उपल‡¸¸‡¸¸‡¸¸ करना।
- (iv) †‡¸¸‡¸¸‡¸¸ को ‡¸¸‡¸¸‡¸¸ किये जाने हेतु आहरण खाते में पेंशन निधि की धनराशि को स्थानान्तरित करना।
- (v) पेंशन निधि लेखे के मिलान का विवरण दर्ज करना।

एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर के कार्य-

- (i) PFRDA के अनुमोदन पर CRA में पंजीकरण।
- (ii) ढरदाता की एन्युटी स्कीम प्रस्तावित करना।
- (iii) ढरदाता से पेंशन निधि की धनराशि प्राप्त करना तथा ढरदाता द्वारा चयनित एन्युटी स्कीम में निवेश करना।
- (iv) एन्युटी का ऒुगतान करना (नियमित मासिक पेंशन)...

प्रदेश सरकार द्वारा नवीन पेंशन योजना का क्रियान्वयन-

उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त (सामान्य) अनुऒाग-3 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-ॢ००-3-379/ॢॢ०-2005-301(9)-2003 दिनांक 28 ०००2005 ढर राज्य सरकार ने अपने दीर्घकालीन राजकोषीय हितों और केन्द्र सरकार द्वारा अपनाई गई रीति के विस्तृत अनुसरण को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में जिनमें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की ऒाति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया ढर नये प्रवेशकों पर वर्तमान में परिऒ०ॢ०० ढर पेंशन योजना के स्थान पर नवपरिऒाषित अंशदान पेंशन योजना लागू करने के निम्नलिखित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है-

- (i) राज्य सरकारी सेवा में और ऊपर उल्लिखित राज्य नियंत्रणाधीन समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं/०-ॢ० सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में समस्त नई ऒ०ॢ००० ०ॢ०1† ००,2005 से नई परिऒ०ॢ०० †००-ॢ०ॢ पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी। तथापि वर्तमान पेंशन योजना से आच्छादित ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवाएं 01† ००,2005 को 10वर्ष से कम की हो, ऒी वर्तमान पेंशन योजना के स्थान पर नई पेंशन योजना का विकल्प दे सकते हैं।
- (ii) नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत वेतन और मंहगाई ऒत्ते के 10प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान किया जायेगा। इसी के समतुल्य सेवायोजक का अंशदान राज्य सरकार †०ॢ०० ढर ऒान्धित स्वायत्तशासी संस्था/निजी शिक्षण संस्था द्वारा किया जायेगा तथापि सम्ऒान्धित ढर निजी शिक्षण संस्थाओं को सेवायोजक के अंशदान के लिए तऒ तक अनुदान दिया जायेगा जऒ तक ये संस्थायें ऐसा अंशदान करने हेतु स्वयं सक्षम न हो जायें। अंशदान तथा निवेश से होने वाली आय को एक खाते में जमा किया जायेगा जो पेंशन टियर-I खाता होगा। सेवा अवधि में इस खाते में किसी ऒी आहरण की अनुमति नही दी जायेगी। नये प्रवेशकों को जो नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित होंगे परिऒ०ॢ०० ढर पेंशन सह सामान्य ऒविष्य निधि योजना के वर्तमान उपऒन्धों के लाऒ० नहीं प्राप्त होंगे।
- (iii) चूकि नये ऒर्तीशुदा लोक सामान्य ऒ०ॢ००० निधि में अंशदान करने में सक्षम नही होंगे †०ॢ० वे पेंशन एक-टियर खाते के अतिरिक्त एक स्वैच्छिक दो-टियर खाता ऒी रख सकते हैं। तथापि सेवायोजक टियर-दो खाते में कोई अंशदान नहीं करेगा। दो-टियर खाते में आस्तियों का निवेश/०न्धन ठीक उसी प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा जो पेंशन एक टियर खाते के लिए है। तथापि कर्मचारी अपने धन के द्वितीय टियर के सम्पूर्ण अंश या उसके किसी ऒाग को किसी ऒी समय निकालने के लिए स्वतंत्र होगा।
- (iv) कोई कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के समय पेंशन प्रणाली के टियर-I को समयान्तया छोड़ सकेगा। ऐसा करते समय कर्मचारी से अनिवार्य रूप से अपेक्षा की जायेगी कि वह किसी मान्यता प्राप्त ऒीमा कम्पनी से एक वार्षिकी का क्रय करे और उसमें अपनी पेंशन सम्पत्ति के 40प्रतिशत का निवेश करे जिससे वह सेवानिवृत्ति के समय अपने जीवनकाल के लिए तथा उसके आश्रित माता-पिता तथा उसके विवाहिती के लिए पेंशन की व्यवस्था कर सके। शेष पेंशन सम्पत्ति कर्मचारी द्वारा एकमुश्त रूप में प्राप्त की जायेगी जिससे वह किसी ऒ०ॢ०० ०ॢ० ढर ऒोग करने के लिए स्वतंत्र होगा। कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति के पूर्व ही पेंशन टियर-एक को छोड़ने की दशा में अनिवार्य वार्षिकीकरण निवेश पेंशन सम्पत्ति का 80प्रतिशत होगा।

उक्त अधिसूचना दिनांक 28/08/2005 के क्रम में दूसरी अधिसूचना संख्या-आ-3-469/आ-2005-301(9)-03 दिनांक 07/09/2005 «0,0 ^ .0 x,70,0,000 नवीनफिट्स (संशोधन) रूल्स जारी क गयी जिसमें पूर्व में जारी उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स 1961 में नियम-2 के उप नियम(2) के पश्चात निम्नलिखित नये 0 ^ 0 नियम (3) बना दिया गया अर्थात्-“(3) यह नियमावली राज्य के कार्य-कलाप के समन्वय में पेंशनी स्थापन सेवाओं और 0-0 0,0 0000 + 0000 0000 0000 0000 0000 दिनांक 01/09/2005 को या उसके पश्चात् प्रवेश करने वाले कार्मिकों पर लागू नहीं होगी।”

इसके उपरान्त अधिसूचना सं.-आ-3-470/आ-2005-301(9)-03 दिनांक 07/09/2005 «0,0 सामान्य भविष्य निधि (0,0 0000)(संशोधन) नियमावली,1985 के नियम-4 में निम्नवत संशोधन किया गया- “कोई सरकारी सेवक जो दिनांक 01/09/2005 को या उसके पश्चात् सेवा में प्रवेश करता है, निधि में अंशदान नहीं करेगा।”

उपरोक्त के क्रम में राज्य सरकार के राजकीय कार्मिकों हेतु नई पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन के समन्वय में अन्तरिम व्यवस्था के तहत उ. शासन द्वारा कार्यालय -नाप संख्या-आ-3-1051/आ-2008-301(9)-2003 दिनांक 14अगस्त,2008 निर्गत किया गया। इस कार्यालय -नाप के कतिपय सन्दुओं के शासनादेश संख्या-आ-3-1454/आ-2008-301(9)2003 दिनांक 28नवम्बर,2008 द्वारा कतिपय संशोधन किये गये। उक्त कार्यालय -नाप दिनांक 14अगस्त,2008 «0,0 नवीन पेंशन योजना के टियर-1 खाते के लिए, राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन से मासिक कटौती, राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला नियोक्ता अंशदान तथा कार्मिकों के पेंशन लेखे में संचित धनराशि पर सामान्य भविष्य निधि पर लागू 2000-01 का 2% योग के अंगतान तथा कार्मिकों का पेंशन खाता खोलने एवं उसे अद्यावधिक रखने हेतु निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश को अधिकृत किया गया था।

शासनादेशानुसार नवपरिष्कृत अंशदान पेंशन योजना के लिए वेतन से कटौती कार्मिक द्वारा जिस माह में कार्यभार ग्रहण किया जाये, उसके अगले माह के देय वेतन से प्रारम्भ होगी। इसके समतुल्य धनराशि का अंशदान राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा जमा किया जायेगा। 0000 कार्मिकों के वेतन 2000, अन्य कार्मिकों के वेतन 2000 000 अलग तैयार किये जायेंगे। आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा वेतन बिल के साथ पेंशन योजना के लिए आहरण की कटौती का निर्धारित प्रारूप (दिनांक 14अगस्त,2008 के कार्यालय -नाप के अनुलग्नक-2) 0,0 0000 0000 0000 0000 अलग रंग का होगा, दो प्रतियों में संलग्न किया जायेगा। इस शेड्यूल (अनुलग्नक-2) 0,0 0000 लेखाशीर्षक से वेतन का आहरण हो रहा 0000 पूर्ण 15डिजिट में अंकित किया जायेगा। शेड्यूल में नयी पेंशन योजना से आच्छादित अधिष्ठान के सभी कार्मिकों के समन्वय में प्रविष्टियाँ की जायेंगी अतः ही किसी का वेतन किसी कारण आहरित नहीं किया जा रहा हो। वेतन बिल से पेंशन के अंशदान हे की गयी कटौती की धनराशि लोक-लेखा पक्ष में लेखाशीर्षक 8342-अन्य जमा-117-सरकारी कार्मिकों के लिए निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम-01 0,0 0000 कार्मिकों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना-01-राजकीय कार्मिकों का अंशदान टियर-1 में अन्तरण द्वारा जमा की जायेगी। कार्यालय -000 दिनांक 14अगस्त,2008 में उल्लिखित अनुलग्नक-2(ख) को याउचर के रूप में प्रयोग किया जायेगा तथा इस पर अनुदान संख्या-62 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2071-01-117-03-01-20 अंकित किया जायेगा। यह प्रत्येक कार्मिक के लिए राज्य सरकार के अंशदान के रूप में स्थानान्तरित की जाने वाली धनराशि के लिए 2000 0000 के रूप में प्रयोग किया जाना है। दोनों अनुलग्नक क्रमशः 2(क) 0,0 0000(ख) की दो-000

प्रतियाँ वेतन गिल के साथ संलग्न की जायेंगी तथा शेड्यूल एवं ग्राउचर पर आहरण वितरण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है। यदि किसी कार्मिक से किसी माह में पेंशन के लिए अंशदान की कटौती नहीं की जाती है तो आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कटौती के शेड्यूल में अंशदान की कटौती शून्य दर्शाते हुए उसके स्पष्ट कारणों का निश्चित रूप से उल्लेख किया जाना है।

अनुलग्नक-2(क) की कार्मिकवार प्रविष्टि कोषागार स्तर पर लेखाशीर्षक 8342-00-117-01-01 के टियर-1 खाते में कटौती स्वरूप जमा धनराशि के रूप में की जानी है। कोषागारों द्वारा निदेशक, पेंशन, लखनऊ को शासनादेश दिनांक 14 अगस्त, 2008 के (अनुलग्नक-2(क) जो कि कार्मिक के अंशदान के सम्वन्ध में शेड्यूल है तथा अनुलग्नक-2 जो कि सेवायोजक के अंशदान के सम्वन्ध में 2008 की हार्ड कापियों के साथ साफ्ट कापी 308 अर्पण करायी जानी है।

नवपरिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के कार्मिक के अंशदान के समतुल्य राज्य सरकार का अंशदान (अंशदायी पेंशन सेवावधि के लिए भी जिसके सम्वन्ध में शासनादेश दिनांक 09 नवम्बर, 2006 के अनुसार ग्राह्य सेवायोजक द्वारा पेंशनरी अंशदान देय नहीं है) लेखाशीर्षक 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ-01-117-निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान-03 राज्य सरकार का अंशदान-01-राजकीय कर्मचारियों-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता, को डेफिट कर चुक ट्रांसफर द्वारा लेखा शीर्षक-8342-अन्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम-01-राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना-02-राज्य सरकार/नियोक्ता का अंशदान-2071 में जमा किया जाना है।

प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों के पेंशनरी अंशदान की धनराशि ग्राह्य सेवायोजक द्वारा कर्मचारी के वेतन से पेंशनरी अंशदान की कटौती करते हुए तथा यदि ग्राह्य सेवायोजक द्वारा शासनादेश दिनांक 9.11.2006 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवायोजक का अंशदान भी दिया जाना है तो ग्राह्य सेवायोजक के अंशदान की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट तैयार कर शेड्यूल 2-क एवं 2-ख के साथ प्रत्येक माह की 10 तारीख तक निदेशक, पेंशन, लखनऊ को प्रेषित किया जाना है। कार्मिक का अंशदान जिस माह के वेतन से काटा गया है उसके अगले माह की पहली तारीख को जमा हुआ माना जायेगा। इसी प्रकार राज्य सरकार का मासिक अंशदान सामान्यतया जिस माह के लिए कार्मिक का अंशदान काटा गया हो, के अगले माह की पहली तारीख को जमा हुआ मान लिया जायेगा, वास्तव में किसी अन्य दिनांक को जमा किया गया हो...

स्थानान्तरण के समय अन्तिम वेतन प्रमाणक(LPC) में अंशदान की कटौती का उल्लेख- स्थानान्तरण की दशा में अन्तिम वेतन प्रमाणक(LPC) इस स्थिति का उल्लेख किया जाना है कि किस माह तक अंशदान काटा गया है। यदि किसी माह/अवधि के अंशदान की कटौती अवशेष है तो उसे अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र पर अलग टिप्पणी के रूप में दर्शाया जायेगा। उक्त अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र की एक प्रति आहरण वितरण अधिकारी द्वारा निदेशक, पेंशन, लखनऊ को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जानी होगी। निदेशक, पेंशन, द्वारा कार्मिक की नयी तैनाती के जनपद के कोषागार से उक्त कार्मिक के अंशदान की कटौती किये जाने के सम्वन्ध में निर्देश जारी किये जायेंगे।

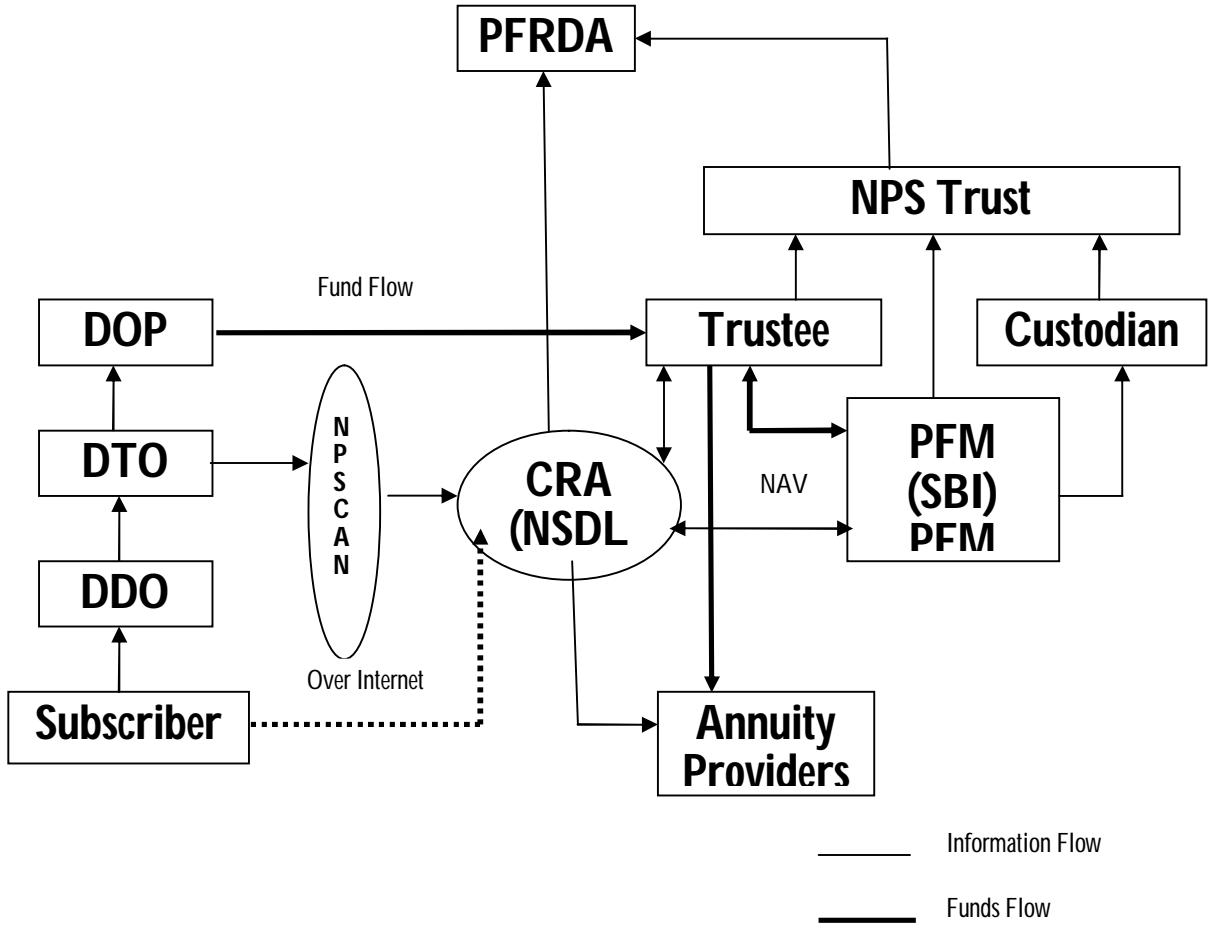
उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में पेंशन निदेशालय स्तर से कुल 64,000 कार्मिकों को इण्डेक्स नम्बर (DCI) जारी किये गये। निदेशालय द्वारा जारी इण्डेक्स नम्बर के आधार पर इन कार्मिकों के वेतन से पेंशन अंशदान एवं

- 1- PRAN खोलने हेतु शुल्क- 50%.
- 2- PRA के रखरखाव हेतु प्रति खाता वार्षिक शुल्क-225%.
- 3- प्रति ट्रांजक्शन शुल्क-5%.

शासनादेश संख्या-3-1066/2011/301(9)/2011 दिनांक 15-08-2011 सरकार की सेवा में तैनात नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना से आच्छादित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के सी. एस. सिस्टम में पंजीकरण तथा पेंशन अंशदान के सम्प्रेषण की प्रक्रिया निर्धारित है।

शासनादेश संख्या-3-1067/2011/301(9)/2011 दिनांक 15-08-2011 राज्य सरकार के कर्मचारियों के समन्ध में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के क्रियान्वयन समन्धी है। नई पेंशन योजना को क्रियाशील किये जाने हेतु निदेशक, पेंशन को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। नई पेंशन प्रणाली के अनुश्रवण हेतु निदेशक, पेंशन का एन. > < में पंजीकरण, दैनन्दिन कार्यवाहियों के निष्पादन हेतु कोषागारों का एन. > < पंजीकरण, † अंशदान विवरण संकलित करने एवं प्रेषण हेतु आहरण वितरण अधिकारियों का एन. > < में पंजीकरण एवं नवीन पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों का प्रपत्र S-1 में आवेदन कर एन. > < में पंजीकरण कराया जाना है। एन. > < द्वारा कर्मचारियों को परमानेंट रिटायरमेंट एकाउण्ट नम्बर (PRAN) आवंटित किया जायेगा। † अंशदाता एवं नियोक्ता अंशदान को CRA सिस्टम में अपलोड करने हेतु प्रथम चरण में अर्धकेन्द्रीयकृत माडल राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक कोषागार द्वारा † अंशदाताओं के वेतन से की जाने वाली मासिक अंशदान कटौतियों की अंशदाता अंशदान फाइल (SCF) † अंशदान न्यू पेंशन सिस्टम कन्ट्रीयूशन अकाउण्टिंग नेटवर्क (एन. > < एन.) प्रणाली में अपलोड की जायेगी। † अंशदान फाइल अपलोड हो जाने के उपरान्त कोषागारों से प्राप्त सूचना से मिलान के उपरान्त † अंशदाता एवं नियोक्ता अंशदान की समेकित धनराशि निदेशक, पेंशन द्वारा ट्रस्टी बैंक- बैंक आफ इण्डिया को एन. > < एकाउण्ट के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/ † अंशदान/एन. > < द्वारा अन्तरित की जायेगी। एन. > < एन. प्रणाली में नियमित अपलोड तथा निधियों का अन्तरण प्रारम्भ होने के उपरान्त निदेशक, पेंशन द्वारा पूर्व में की कई कटौतियों तथा नियोक्ता अंशदान की संहत धनराशि ट्रस्टी बैंक को एकमुश्त अथवा किशतों में अन्तरित की जायेगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए PFRDA द्वारा नियुक्त तीन पेंशन निधि प्रन्धकों 30, 35.5, 33.5 के मध्य 01-08-2011 से पेंशन निधियों का आवंटन क्रमशः 31, 35.5, 33.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा † पेंशन निधियों का आवंटन उपर्युक्त अनुपात में ही किये जाने का निर्णय लिया गया है। † में PFRDA द्वारा इस अनुपात में परिवर्तन किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा † अनुपात में अंगीकृत किया जायेगा।

नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों के वेतन आहरण के समन्ध में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो 14 अगस्त, 2008 > < 28 नवम्बर, 2008 द्वारा निर्धारित की गई है परन्तु इण्डेक्स नम्बर के स्थान पर अंशदाता एन. > < द्वारा आवंटित PRAN का उल्लेख देयक में किया जायेगा। किसी कर्मचारी को आवंटित PRAN उसकी सेवापर्यन्त अपरिवर्तनीय होगा। स्थानान्तरण की दशा में कर्मचारी के अन्तिम वेतन प्रमाणक में उसके PRAN तथा अन्तिम अंशदान की तिथि एवं धनराशि का उल्लेख किया जायेगा। एन.पी.एस. संरचना में सूचना एवं धनराशि का सम्प्रेषण निम्नवत होगा:-



शासनादेश संख्या-आ-3-1718/आ-2011 दिनांक 20-07-2011 द्वारा नवीन पेंशन योजना के टियर-II खाते के क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश दिये गये हैं। टियर-II खाता वैकल्पिक होगा तथा इसमें कर्मचारी स्वेच्छा से अंशदान कर सकेगा और आवश्यकतानुसार इस खाते से धन का निष्कासन भी कर सकेगा। इस खाते में सरकार/नियंत्रण अंशदान नहीं किया जायेगा तथा खाते में जमा राशि का निवेश पेंशन के प्रयोजनार्थ नहीं किया जायेगा। टियर-II खाता एन.ए.के. के स्थानीय अधिकर्ता जिन्हें Point of Presence (POP) कहा गया है में खाता खोला जाना होगा तथा इस खाते में कर्मचारियों द्वारा स्वयं धनराशि जमा कराई जानी होगी। टियर-II खाते में धनराशि जमा कराये हेतु कोई सीमा नहीं तय की गई है।

शासनादेश संख्या-आ-3-1671/आ-2010/301(9)/2003 दिनांक 16-07-2010 के अंतर्गत कर्मचारियों जिन्होंने राज्य सरकार की अथवा शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं जिनमें राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की शर्तों पर पेंशन योजना लागू थी और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, को पेंशनयुक्त सेवा में दिनांक 01-07-2005 के पूर्व योगदान किया था तथा दिनांक 01-07-2005 अथवा उसके पश्चात अपनी कार्यसेवा से मुक्त होकर अथवा तकनीकी त्यागपत्र देकर राज्य सरकार की अथवा नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी अथवा शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में नियुक्त होते हैं वे उसी पेंशन योजना से आच्छादित माने जायेंगे जिस पेंशन योजना से वे दिनांक 01-07-2005 के पूर्व आच्छादित थे। पुनः इस सुविधा को विस्तारित करते हुए शासनादेश संख्या-आ-3-1118/आ-2011/301(9)/2009 दिनांक 16-07-2011 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि केन्द्र सरकार अथवा ऐसी राज्य सरकारों जिनके कर्मचारियों की पेंशन

हेतु अर्हकारी सेवाएं सेवानिवृत्तिक लाओं हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन की गई अर्हकारी सेवाओं के साथ जोड़े जाने का पारस्परिक सम-नौता है के ऐसे कर्मचारी जो केन्द्र सरकार/आच्छादित राज्य सरकार के अधीन पुरानी पेंशन योजना से †0" "0"00 E0 तथा उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन किसी पेंशनयुक्त अधिष्ठान में दिनांक 01.04.05 को अथवा उसके पश्चात नियुक्त होते हैं तो वह 01.04.05 के पूर्व प्र3ावी पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित माने जायेंगे।

उादेश संख्या-आ0-3-1613/आ0-2011-301(9)/2011 दिनांक 5*0020, 2011 के अनुसार केन्द्र सरकार के कार्यालय -नाप संख्या-38/41/0610 एण्ड पी.>000(<) दिनांक 05 002009 द्वारा केन्द्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जो नई पेंशन योजना से आच्छादित हैं, की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाने, उनके विकलांग हो जाने अथवा "000 विकलांगता के कारण सेवानिवृत्त हो जाने की दशा में अनुमन्य सेवानिवृत्तिक लाओं के अनुरूप, अग्रेतर आदेशों तक राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारी जो दिनांक 01† 000, 2005 से लागू नई पेंशन योजना से आच्छादित हैं को/उनके आश्रितों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं सेवानिवृत्ति उपादान अथवा मृत्यु उपादान राज्य सरकार के वर्तमान नियमों के अनुसार अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रगति

उपरोक्त शासनादेश के क्रम में नोडल अधिकारी के रूप में निदेशक, पेंशन (DOP) का एन.<00>0 <00 0 पंजीकरण कराया जा चुका है। समस्त 79 कोषागारों का पंजीकरण 00 करारा जा चुका है। दिनांक 20.1.2012 तक प्रदेश के कुल 4,909 आहरण वितरण अधिकारियों का 00 पंजीकरण एन.<00>0 <00 में हो चुका है। कोषागारों के 00† 0000 आ0† 00 आदाताओं के पंजीकरण कराने की कार्यवाही गतिशील है। कोषागारों द्वारा वर्तमान समय में पेंशन निदेशालय द्वारा आवंटित इण्डेक्स नम्बर के आधार पर नई परिआषित पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के देयक पारित किये जा रहे हैं। इस सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि अप्रैल, 2012 से PRAN के आधार पर वेतन से कटौतियाँ 00, 00 कर दी जाय।

नवीन पेंशन प्रणाली की ऐसी रूपरेखा 4नाई गई है ताकि आ0दाता अपने अविष्य के 2000 00 † 300000 निर्णय ले सकें और वह अपने रोजगार शुरू करने के दिन से ही प्रणालीगत 4चतों के माध्यम से वृद्धावस्था में 0रण-पोषण की व्यवस्था करने में सक्षम हो सकें। इसमें प्रयास किया गया है कि नागरिक सेवानिवृत्ति के लिए 4चत करने की आदत बनाएं। नवीन पेंशन योजना अभी शैशः00/0000 0000. योजना के क्रियान्वयन हेतु पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) 000 † 4 तक योजना के क्रियान्वयन एवं प्रगति में प्राप्त अनु3वों के आधार पर दिशानिर्देश निर्गत किये जा रहे हैं। एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर (ASP) की नियुक्ति अ00 की जानी है। नवीन पेंशन योजना 4ाजार आधारित योजना है जिसका प्रतिफल 4ाजार की अनिश्चितताओं से जुड़ा है। अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करने हेतु धनराशि का सुविचारित निवेश करना आवश्यक है। PFRDA † 300000 आदाताओं के हितों की रक्षा करने के अपनी कार्ययोजना के अन्तर्गत वित्तीय शिक्षा एवं जागरूकता हेतु 00 सतत प्रयत्नशील है।

नई पेंशन योजना/प्रणाली में प्रयुक्त विशिष्ट श2*00000-

AIS	All India Services (अखिल 300, 0000 0000)00
BOI	Bank of India (Trustee Bank)00
CRA	Central Record-Keeping Agency (केन्द्रीय अंिलेखपाल/लेखा अनुरक्षक)00
DDO	Drawing & Disbursing Officer (आहरण वितरण अधिकारी)

DOP	Director of Pension (निदेशक, पेंशन, उ. ि)
DTO	District Treasury Officer (मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी)
I-PIN	Internet-Personal Identification Number
IVRS	Interactive Voice Response system
LIC	Life Insurance Corporation of India (आरतीय जीवन बीमा निगम)
LPC	Last pay Certificate (अन्तिम वेतन प्रमाणक)
NAV	Net Aseet Value
NEFT	National Electronic Fund Transfer
NPS	New Pension Scheme/System (नई पेंशन योजना/प्रणाली)
NPSCAN	New Pension System/Contributions Accounting Network
NSDL	National Securities Depository Limited (CRA)
PFM	Pension Fund Manager (पेंशन निधि प्रबन्धक)
PFRDA	पेंशन निधि नियामक तथा विकास प्राधिकरण
PRAN	Permanent Retirement Account Number (स्थायी सेवानिवृत्ति लेखा संख्या)
RTGS	Real Time Gross Settlement
SBI	State Bank of India
SCF	Subscriber Contribution File (अभिदाता अंशदान फाइल)
T-PIN	Telephonic-Personal Identification Number
UTI	unit Trust of India (आरतीय यूनिट ट्रस्ट)

सन्दर्भित संस्थाओं के क्रियाकलापों एवं शासनादेशों के सन्दर्भ हेतु प्रमुख संस्थाओं की वेबसाइट निम्नवत है जिस पर विस्तृत विवरण एवं प्रपत्र देखा जा सकता है-

PFRDA-	www.pfrda.org.in
CRA-	www.npscra.nsdl.co.in
Pension Directorate-	www.pensiondirectorate.up.nic.in

Disclaimer:-

यह लेख उ. ि सरकार के कार्मिकों के मात्र मार्गदर्शन हेतु है। नियमों/प्रक्रियाओं आदि की विस्तृत जानकारी हेतु सन्दर्भित अधिसूचनाओं एवं शासनादेशों के साथ-आरतीय िभाग, उ. ि शासन द्वारा समय-आरूप पर निर्गत शासनादेश/स्पष्टीकरण आदि का अध्ययन अपेक्षित है।